(ख) और (ग) चूंकि खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के कुछ कर्मकार पूर्णकालिक आधार पर कार्य करते हैं और कुछ अंशकालिक आधार पर इसलिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग संस्थानों द्वारा अपनाये जाने के लिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग ने उजरती दर के आधार पर मजदूरी की एक पद्धति निर्धारित की है, मजदूरी की राशि मजदूरी की निर्धारित उजरती दर के अनुसार कर्मकारों द्वारा किये गये कार्य पर निर्भर करती है। ग्रामीण उद्योगों के मामले में सहयोगी क्षेत्र के अधिकतम संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक प्रत्येक उद्योग में तथा कार्यकलाप के अनुसार अलग-अलग होता है। तथा प, ग्रामीण उद्योग में किसी शिल्पी की दैनिक औसत आय लगभग 20/–रु० (बीस रुपये) प्रति दिन है।

(घ) जी, हां। खादी क्षेत्र में उत्पादित सामान को कई देशों में निर्यात किया जाता है। वर्ष 1989–90 के दौरान के०वी०आई० उत्पाद का निर्यात बढ़कर 5.54 करोड़ रुपये का हो गया जबकि यह वर्ष 1988–89 के दौरान, 5.05 करोड़ रुपये का था।

(ङ) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग समय-समय पर के०वी०आई० क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा लगाये गये कर्मकारों की मजदूरी की दर की पुनरीक्षा करता है। मूल्य सूचकांक के स्तर में सामान्यतः वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी में वृद्धि कर दी जाती है।

सन् 2025 तक सभी व्यक्तियों को रोजगार

1523. श्री राम जेटमलानी :

सरदार दलजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2025 को उस वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है जिस तक रोजगार के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ख) यदि हां, तो रोजगार के इच्छुक ऐसे युवा व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है और उस समय तक सृजित किए जाने वाले रोजगार अवसरों की अपेक्षित संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वार्षिक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, नहीं। आठवीं योजना दृष्टिकोण दस्तावेज में परिकल्पित, 1990 के दशक की समाप्ति तक रोजगार के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर, सन् 2000 तक लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य पर आधारित है। चालू दशक के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगों की संख्या जिनको रोजगार मुहैया कराना है तथा इसी तरह सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित रोजगार अवसरों की संख्या लगभग 106 मिलियन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें आठवीं योजना दस्तावेज में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई की प्रतिष्ठापित क्षमता

1524. श्री राम जेटमलानी :

सरदार दलजीत सिंह अरोड़ा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई की मौजूद प्रतिष्ठापित

क्षमता राज्य में गन्ने के उत्पादन की तुलना में पर्याप्त नहीं है जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) 1989-90 के मौसम के दौरान महाराष्ट्र के चीनी कारखानों ने 365.8 (अनंतिम) लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की थी। महाराष्ट्र में इस मौसम में गन्ने के उत्पादन के बारे में ठोस अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शीघ्र पेराई के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन में वृद्धि करने तथा शीघ्र पेराई के लिए मंजूर प्रोत्साहन की ही तरह मौसम के दौरान तथा मौसम के अंत में पेराई के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

पेराई के लिए प्रोत्साहनों की मंजूरी का मिल की वित्तीय जीव्यता से संबंध होता है, किंतु ये पेराई की क्षमता को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। तथापि, सरकार स्थिति की कड़ी निगरानी कर रही है।

Statement of Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi

1535. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi had in a statement urged for the deployment Of United Nations forces in India for the protection of minorities; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) Such a statement has come to the notice of the Government. The Delhi Administration is taking appropriate action in the matter.

दिल्ली पुलिस को राशन भत्ता

1536. श्री लक्खीराम अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को सस्ती दर पर राशन प्रदान कराने के बजाय 200/-रु० प्रतिमाह राशन भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने अपने कार्मिकों को राशन भत्ता देने के लिए दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है।

NaxSWies in Aadhra Pradesh.

1537. SHRI KAILASH NARAYAN SARANG: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether terrorist activities of the People's War Group (PWC) in Andhra Pradesh are on the increase and are spreading from there to the neighbouring Maharashtra as reported in the Hindu dated